नियोजन विभाग की नवनिर्मित वेबसाइट (planning.up.nic.in) पर अपलोड करने हेतु दीर्घकालीन योजना प्रभाग] का विवरण

1- संगठन

नियोजन विभाग के अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी। प्रदेश के वृहत आकार एवं जनसंख्या] गरीबी] बेरोजगारी तथा आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ी पेचीदा एवं विकराल समस्याओं तथा वित्तीय संसाधनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुयी अभावग्रस्तता की स्थिति में राज्य सरकार ने गम्भीरतापूर्वक अनुभव किया कि इनका अपेक्षित समाधान विकास के सुनियोजित दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ही संभव हो सकता है] जिसके अन्तर्गत सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं अन्तर्क्षेत्रकीय निर्भरता सुनिश्चित करते हुये अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण समाजार्थिक क्रियाकलापों के समुचित विकास हेतु एक दीर्घकालीन परिदृश्य बनाया जा सके और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को आवश्यकतानुसार सही दिशा एवं गति प्रदान की जा सके।

2- संगठनात्मक ढांचा

दिनांक 01-10-2023 तक स्टाफ की स्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान			स्वीकृत पद (सं0)	भरे पद (सं0)	रिक्त पद (सं0)
		वेतन बैण्ड (रू0 में)	ग्रेड वेतन (रू0 में)	लेवल			
	राजपत्रित						
1	निदेशक	37400-6700	8700	13	1	1	-
2	संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	12	2	1 *	1
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी	15600-39100	6600	11	4	3	1
4	शोध अधिकारी	15600-39100	5400	10	8	4	4
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4600	7	18	-	18
	अराजपत्रित						
1	शोध सहायक (अभियंत्रण)	9300-34800	4600	7	-	1 **	-
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300-34800	4200	6	3	3	-
3	वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	7	11	2	
	आशुलिपिक	5200-20200	2800	4		-	9
4	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	4	2	-	2
5	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	3	3	3 *	-
6	कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-1	5200-20200	2400	3	1	-	1
7	चपरासी/स्वीपर कम-फरार्श	5200-20200	1800	3	4	2	2

नोट- * एक संयुक्त निदेशक एवं एक कनिष्ठ सहायक भूमि उपयोग परिषद से सम्बद्ध है।

** एक शोध सहायक (अभियंत्रण) प्रतिनियुक्ति पर ।

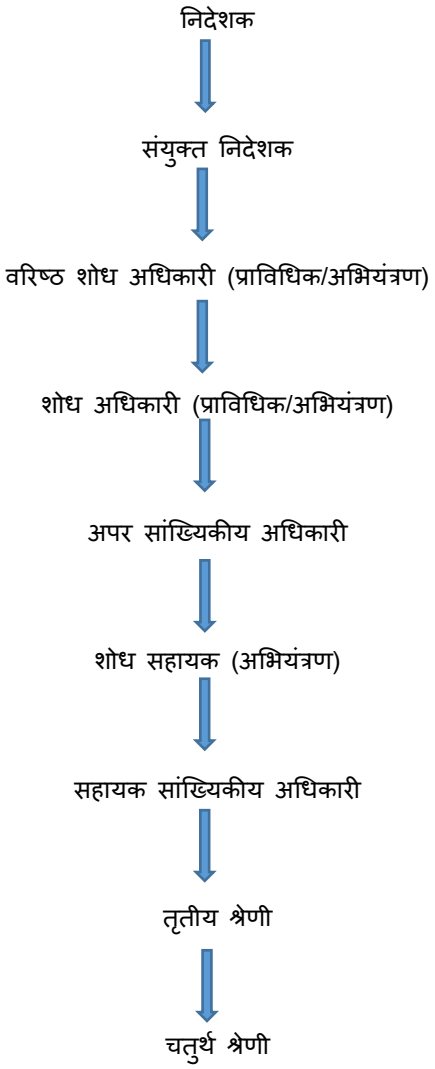

3- उद्देश्य

प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है] जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस उद्देश्य के अनुरूप] राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुये प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवरआल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि-दर आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय] संभावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन] उपभोग] विनियोग] बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन अनुपात] पूंजी-उत्पादन अनुपात] विकास-रणनीति आदि) से संबंधित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्वपूर्ण कार्य है।

अस्तित्व में आने के पश्चात् योजना संरचना में व्याप्त तदर्थता पर पूर्ण विराम लगाना प्रभाग के समक्ष प्रमुख कार्य था। प्रदेश के विकास का एक संतुलित दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिये प्रभाग ने बहुआयामी

एवं व्यापक अध्ययन सम्पादित कर उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित रिक्तता को भरने का प्रयास किया गया। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की मूल संरचना का अध्ययन करने हेतु प्रभाग ने निम्नलिखित प्रकार के अध्ययन सम्पादित किये हैं।

(क)-संरचनात्मक एवं पैरामीट्रिक अध्ययन

(ख)-योजना परिप्रेक्ष्य विषयक अध्ययन

(ग)-क्षेत्रकीय अध्ययन

(घ)-विविध अध्ययन

4- प्रभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में सम्पादित/सम्भावित अध्ययनों/कार्यो का विवरण:-

प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले **कार्य**	**समय - सारणी**
I- **एस0एस0एस0 योजनान्तर्गत यू0एन0डी0पी0 द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य कार्यो का विवरण-** 1- Implementation of recommendation of Technical Groups/Bodies for filling up existing/emerging data gaps including of State. 2- HRD Issues, with a focus on training for capacity development and skills enhancement/up gradation, including support to regional training center. 3- Holding of regular/periodic (say once every year) user, producer dialogue, stakeholder consultation and conduct of periodic surveys on user satisfaction. 4- Dissemination of Annual reports on the performance of state statistical systems and improving the cost effectiveness and ease of data access. 5- Data quality and efficiency improvement measures(strengthening monitoring frame work for sustainable development goals SDG)	समयानुसार * (प्रतिलिप संलग्न)
2- एस0डी0जी0 सम्बन्धी कार्य- • इण्डिया एस0डी0जी0 इण्डेक्स-4.0 • एक्शन प्लान • मास्पी प्रगति रिपोर्ट • जनपद स्तर/मण्डल स्तर पर कार्य • कैपिसिटी बिल्डिंग • बैठकों का आयोजन • कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में प्रतिभाग • नीति आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं कृत कार्यवाही • लोकलाइजेशन आ**W**फ एस0डी0जी0 के तहत् एच0पी0सी0 **(Highlevel Steering Committe)** के संबंध में कार्यवाही	समयानुसार
3- इंडीकेटर्स सेल (कॉल सेन्टर)- • एस0आई0एफ0/डी0आई0एफ0 • नीति-मॉस्पी इंडीकेटर्स/डैशबोर्ड • जनपदों से वार्ता/प्रशिक्षण	समयानुसार
4- ई-समीक्षा का कार्य।	समयानुसार

5- नक्सल संबंधी कार्य।	समयानुसार
6- इनोवेशन सम्बन्धी कार्य।	समयानुसार
7- **बेस्ट प्रैक्टिसेज एवं अभिनव प्रयोग से संबंधित कार्य-** नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित बेस्ट प्रैक्टिसेज को प्रदेश के जनपदों/विभागों को परिचालित करना।	समयानुसार
8- विभागीय वेबसाइट संबंधी कार्य	समयानुसार
II - **अध्ययन संबंधी कार्य:**	
1- वर्ष 2021-22 के आय-व्यय की संरचना	मार्च, 2024
2- गवर्नेन्स विषयक अध्याय तैयार करना- (1) Good Governance, (2) Private Public Partnership (PPP), (3) Disaster Management, (4) Local Self Govt.	मार्च, 2024
III-**वर्ष 2023-24 में कराये जाने वाले अन्य कार्य:**	
1- सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन से संबंधित कार्य।	समयानुसार
2- अ-समय-समय पर प्रेषित विभिन्न प्रशिक्षुओं को नियोजन संबंधी विषय पर अभिज्ञान करना। **ब-**सतत् विकास लक्ष्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रभाग, कालाकांकर भवन में प्रशिक्षण चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देना।	समयानुसार
3- नामित सदस्य के रूप में विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करना।	समयानुसार
4- स्टाफ बैठक।	समयानुसार
5- शासन स्तर पर समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।	समयानुसार

****

सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)

25 सितम्बर, 2015 यूनाइटेड नेशंस (यू0एन0) में आयोजित ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व के 193 देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सतत् विकास लक्ष्य एजेण्डा 2030 (SDG-2030) अपनाया गया, जो दिनाँक 01 जनवरी, 2016 से आधिकारिक रूप से लागू हुआ। वैश्विक स्तर पर इस एजेण्डा 2030 के अन्तर्गत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स (SDGs) 169 टार्गेट एवं 232 ग्लोबल इंडीकेटर फ्रेमर्वक (GIF) विकसित किए गए हैं। जिनका सतत् अनुश्रवण वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। सतत् विकास लक्ष्य एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है। जो सबके लिए समान, न्यायपूर्ण और सुरक्षित विश्व की सृष्टि करेगा। व्यक्तियों, पृथ्वी और समृद्धि के लिए एस0डी0जी0 के मुख्य सिद्धान्त 5 पी (सब लोग, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी) पर आधारित है। प्रदेश स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) के क्रियान्वयन, प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु नियोजन विभाग नोडल विभाग के रूप में नामित है।

सतत् विकास लक्ष्यों की अवधारणा विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों की अन्तर-सम्बध्दता के बारे में दुनिया भर में बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संकल्पित की गयी है। उभरती परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में महसूस किया गया कि विकास से सम्बन्धित समस्याएँ राष्ट्रीय नहीं हैं, बल्कि तेजी से वैश्विक हो रही है। एक देश में जो होता है वह दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वह गरीबी हो या पर्यावरण का क्षरण। ये सभी मुद्दे प्रकृति में सीमा रहित बन रहे है। इसलिए एस0डी0जी0 की पृष्ठभूमि वैश्विक समस्याओं की अन्तर निर्भरता पर आधारित है।